समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 09 September 2026

पुराने वाहनों पर नई मार : सरकार करेगी फिटनेस टेस्ट शुल्क मे भारी बढ़ोतरी, ट्रकों के लिए 25,000 रुपये, कारों के लिए 2,600 रुपये

Publisher

Published on 12 Sep 2025

सरकार पुराने वाहनों की फिटनेस जांच (Fitness Test) शुल्क में **भारी बढ़ोतरी** पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत **बड़े ट्रकों के लिए शुल्क 25,000 रुपये** और **कारों के लिए 2,600 रुपये** तक हो सकता है।

यह कदम सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। हालांकि, वाहन मालिकों और व्यापारियों के बीच इस योजना को लेकर चिंता और विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं।

प्रस्तावित शुल्क बढ़ोतरी का विवरण

- **व्यावसायिक ट्रक और भारी वाहन :** फिटनेस टेस्ट शुल्क 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है।
- **प्राइवेट कारे और हल्के वाहन :** शुल्क 2,600 रुपये तक निर्धारित किया जा सकता है।
- **बाइक और स्कूटर :** छोटे वाहनों के लिए भी मामूली बढ़ोतरी की संभावना है।

सरकार का तर्क है कि यह बढ़ोतरी पुराने वाहनों को सड़क से हटाने और नए, प्रदूषण कम करने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है।

वाहन मालिकों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह उनके लिए वित्तीय भार बढ़ा देगा। विशेष रूप से छोटे व्यवसाय और परिवहन उद्योग पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

एक ट्रक मालिक ने कहा, “*[illegible] 25,000 [illegible]*

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□”

सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से:

1. **पुराने और प्रदूषणकारी वाहन कम होंगे।**
2. **सड़क सुरक्षा मे सुंधार होगा।**
3. **नवीनतम वाहनों की खरीद बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।**

मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इसे लागू करने से पहले **सार्वजनिक और व्यापारिक हितधारकों की राय** ली जाएगी।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार यह कदम उठा रही है। पुराने वाहनों में **इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम कमजोर** हो चुके होते हैं, जिससे दुर्घटना और प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि **फिटनेस टेस्ट शुल्क बढ़ाने से पुराने वाहनों की संख्या घटेगी**, और नई तकनीक वाले वाहन सड़क पर आएंगे।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

- **व्यवसाय प्रभावित :** छोटे ट्रक और बस ऑपरेटरों को अतिरिक्त खर्च झेलना पड़ सकता है।
- **नौकरी पर असर :** परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
- **नई वाहन खरीद को बढ़ावा :** कई लोग पुराने वाहन बदलकर नए वाहन खरीदने के लिए प्रेरित होंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम लंबी अवधि में सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए लाभकारी होगा, लेकिन शुरू में वाहन मालिकों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

सरकार ने उद्योग प्रतिनिधियों और राज्य परिवहन विभागों से **फिटनेस टेस्ट शुल्क बढ़ोतरी पर सुझाव** मांगे हैं। इसके तहत **आर्थिक स्थिति, वाहनों की उम्र और सड़क सुरक्षा** को ध्यान में रखा जाएगा।

सरकार का उद्देश्य है कि बढ़ोतरी **सभी के लिए संतुलित और लागू करने योग्य** हो, ताकि व्यवसाय और सार्वजनिक हित दोनों की रक्षा हो सके।

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो आने वाले सालों में भारत के **सड़कों पर पुराने वाहन कम** होंगे और नया, प्रदूषण कम करने वाला वाहन नेटवर्क विकसित होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम **भारत की मोटर वाहन नीति और सड़क सुरक्षा मिशन** के अनुरूप है और लंबी अवधि में आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ देगा।

पुराने वाहनों पर फिटनेस टेस्ट शुल्क में बढ़ोतरी की योजना सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और नए वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, छोटे व्यवसाय और वाहन मालिकों के लिए यह वित्तीय चुनौती होगी। अब यह देखना होगा कि सरकार **संतुलित शुल्क और राहत उपायों** के साथ इस प्रस्ताव को कैसे लागू करती है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.